जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 37 प्रभात अजमेर, गुरुवार 5 सितम्बर, 2024 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

राजस्थान पुलिस फोर्स में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा

मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल ने महिलाओं, विशेष योग्यजन, वृद्ध कल्याण के महत्वपूर्ण फैसले लिये

- **यह भी निर्णय लिया गया कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य नहीं होने पर विशेष योग्य बच्चों, आश्रित माता-पिता तथा विशेष योग्य भाई-बहनों के नाम पैन्शन ऑर्डर में जुड़ सकेंगे।**
- **तीन हजार मैगावॉट सौर ऊर्जा के लिये जैसलमेर की रामगढ़ तहसील में तथा 150 मैगावॉट सौर ऊर्जा के लिये फतेहगढ़ में भूमि आवंटन का निर्णय भी लिया गया।**

जयपुर, 4 सितम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में महिला सशक्तिकरण, विशेष योग्यजन एवं वृद्धजन कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा तथा विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले "आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र-2023" में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भर्ती करने का वादा किया था। इसी संबंध में आज मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा इस बारे में शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। साथ ही, महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य कर सकेगी।

डॉ. बैरवा ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य नहीं होने पर, विशेष योग्य बच्चों, आश्रित माता-पिता तथा विशेष योग्य भाई-बहनों के नाम पैंशन पेमैंट ऑर्डर में जुड़ सकेंगे।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान 70 से 75 वर्ष तक के पैंशनर एवं पारिवारिक पैंशनर के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी। इस क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पैंशन नियम, 1996 के नियम 54बी को प्रतिस्थापित किए जाने की मंजूरी भी आज कैबिनेट में दी गई।

विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य सरकार बिजली उत्पादन बढ़ा कर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में आज कैबिनेट की बैठक में 3 हजार 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृतियां दी गईं। उन्होंने बताया कि "क्रिस्टलाइन टैक्नॉलजी विद ट्रैकर" पर आधारित 3000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नं.-1 में लगाई जाएगी तथा इस प्रोजैक्ट के लिए 6877.66 हैक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

पटेल ने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों में 2 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के संबंध में खिलाड़ियों की परिभाषा को सुस्पष्ट करने के लिए 21 नवम्बर, 2019 को अधिसूचना जारी की गई थी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संबंध में इस स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किए जाने के समय यह प्रावधान दो सेवा नियमों, राजस्थान लैंग्वेज एण्ड लाइब्रेरी (स्टेट एण्ड सबॉर्डिनेट) सर्विस रूल्स, 2013 एवं राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी (स्टेट एण्ड सबॉर्डिनेट) सर्विस रूल्स, 2015 में सम्मिलित किए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आर्थिक स्थिति अच्छी होना बच्चे की कस्टडी पाने का आधार नहीं'

- **राजस्थान हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए दुबई में बसे पिता को बच्चे की कस्टडी सौंपने से इन्कार कर दिया, पर, कहा कि पिता अपने बच्चे से मिल सकता है।**

जयपुर, 4 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दुबई में बसे पिता को सात साल के बच्चे की अभिरक्षा मां से लेकर उसे दिलवाने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने कहा कि ऐसा करना बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। अदालत ने कहा कि पिता के वित्तीय हालात इस बात को तय करने में निर्णायक नहीं हो सकते कि बच्चे की अभिरक्षा उसे सौंपी जाए। हालांकि अदालत ने पिता को बच्चे से मिलने -जुलने की छूट दी है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

पिता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर कहा था कि उसकी पत्नी ने उसके नाबालिग बच्चे को अवैध तौर पर अपनी अभिरक्षा में रखा हुआ है, जबकि उसका बेटा दुबई में पैदा हुआ था और वहां पर सामान्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जनता नाखुश सी नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट की भूमिका से

- **कलकत्ता हाई कोर्ट संषोजजनक तरीके से सुन रहा था, महिला डॉक्टर के "रेप" व हत्या के मामले को, पर, "अकारण" सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानान्तरित कर लिया।**
- **अतः स्वाभाविक तौर पर इस घटनाक्रम के बारे में हाई कोर्ट को सुनवाई रोकनी पड़ी।**
- **पर, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख खिसका दी।**
- **जनता इस पूरे घटनाक्रम को संदेह की दृष्टि से देख रही है, क्योंकि उसे रेप व हत्या के मामले की फाइलों को दफन करने की यह साजिश लग रही है।**
- **बहरहाल जनता ने अपनी नाराज़गी जताते हुए रात को सभी दुकानों व घरों में बत्तियाँ बुझाने का निर्णय लिया।**
- **रात्रि के अंधेरे में सड़कों पर जगह-जगह लोग इकट्ठा होकर टैगोर के गीत गाते हुए सुनाई दिये।**

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। कोलकाता शहर पूरी रात अंधेरे में डूबा रहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पर ऐसा हुआ और कोलकाता 9 अगस्त की रात को युवा मेडिकल छात्रा के साथ हुए रेप तथा मर्डर को लेकर न्याय की माँग के लिए अँधेरे में डूबा रहा। आर.जी.कार. मेडिकल कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल छात्रा के हत्यारों की गिरफ्तारी के मामले में राज्य सरकार की निष्क्रियता को लेकर कोलकाता नगर में उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक लाइट ऑफ करके विरोध किया गया।

इस राज्यव्यापी विरोध के बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने रेप और हत्या के इस केस की सुनवाई आगे के लिए टाल दी है। लोग इस बात की भी आलोचना कर रहे हैं कि इस केस की सुनवाई हो रही थी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को अपने हाथ में क्यों लिया था।

लोग सर्वोच्च न्यायालय से कहीं ज्यादा विश्वास कलकत्ता उच्च न्यायालय पर व्यक्त कर रहे हैं। जब लोग न्याय की माँग कर रहे हैं, ऐसे समय में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस के मामले में जो तौर-तरीका प्रदर्शित किया है, उससे लोग निराश हुए हैं।

इन स्वप्रेरित विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व राज्य के वरिष्ठ डॉक्टर कर रहे हैं उनके सैनिकों की भूमिका जुनियर डॉक्टर निभा रहे हैं। जनता विरोध प्रदर्शन कर रहे इन लोगों के साथ एक परिवार की तरह खड़ी हो गई है।

जनता स्व-प्रेरणा से विरोध करने के लिए सड़कों पर आ गई है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने आर.जी.कार में हुई हत्या के इस केस को जिस तरह से हैंडल किया है, उसकी कड़ी आलोचना कर रही है। पूरे बंगाल की जनता अपना रोष जताने के लिए सड़कों पर आ गई है। जनसामान्य ने अपने घरों की लाइटें बुझा दी तथा सड़कों पर आ गए तथा अपराधियों को बचाने में मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर, जोर-जोर से उनके इस्तीफे की माँग करने लगे। इस बात पर विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि कोलकाता पुलिस और प्रशासन अपनी ड्यूटी निभाने में असफल रहे हैं तथा उन्होंने अपराध से सम्बन्धित सारे साक्ष्य मिट जाने दिए।

इस केस में सुनवाई को रोक देने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नायडू आंध्र में भारी जीत के बाद तेलंगाना में जड़ें जमाना चाहते हैं

पर, उन्हें सफलता मिलेगी इसकी संभावना काफी क्षीण है

- **तेलुगूदेशम का तेलंगाना के कुछ भागों में थोड़ा बहुत प्रभाव है, पर, पार्टी इतनी मजबूत नहीं है कि राज्य की राजनीति में अहम् भूमिका निभा सके।**
- **बी.आर.एस. के उत्थान के साथ ही तेलुगूदेशम पार्टी तेलंगाना में शून्य पर आ गई थी, पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता बी.आर.एस. में चले गए थे।**
- **अब नायडू तेलंगाना में अपनी पार्टी को पुनः स्थापित करना चाहते हैं और इसकी शुरुआत वे हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में जोर आजमा कर करना चाहते हैं।**

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 अगस्त। आन्ध्र प्रदेश में जबसे चन्द्रबाबू नायडू सत्ता में आए हैं उनका ग्राफ ऊपर ही बढ़ता जा रहा है और अब उन्होंने तेलंगाना में भी अपनी पार्टी को मजबूत कराने का इरादा जताया है।

यह संयोग ही है कि तेलगाना में कभी तेलुगूदेशम का कांग्रेस से गठबंधन था। पर इस गठबंधन को के.चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति ने हरा दिया था, उसके बाद कांग्रेस व तेलुगुदेशम का गठबंधन भी टूट गया। हालांकि तेलंगाना के कई भागों में तेलुगूदेशम का वजूद था पर वह इतनी मजबूत नहीं थी कि बी.आर.एस. को चुनौती दे सके। विपक्ष का रिक्त स्थान जल्दी ही कांग्रेस ने अधिग्रहित कर लिया। हालांकि एक बार तो भाजपा राज्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरने लगी थी, पर भाजपा और बी.आर.एस. के बीच पर्दे के पीछे की सांठगांठ का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। उल्लेखनीय है कि उस समय भाजपा ने अपने तेज तर्रार नेता बंडी संजय को हटाकर केन्द्रीय मंत्री जी.किशन रेड्डी को प्रदेश प्रमुख बना दिया था, जिसके बाद विधानसभा चुनाव में भाजपा का भी सफाया हो गया और बी.आर.एस. भी सत्ता से बेदखल हो गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई।

वर्तमान में बी.आर.एस. सत्ता से बाहर है और लोकसभा में भी उसका एक भी सदस्य नहीं है। बी.आर.एस. का राजनैतिक स्थान खाली है और भाजपा एवं तेलुगूदेशम उसे भरना चाहती हैं। खासकर आंध्रप्रदेश में जीत के बाद नायडू तेलंगाना में भी अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं।

हैदराबाद में एच.टी.आर.ट्रस्ट भवन के हुई पार्टी का मीटिंग में नायडू ने कहा कि वे पार्टी को पुनर्जीवित करेंगे,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'होम लोन के बीमा कवर पर वसूली सेवा दोष'

- **उपभोक्ता आयोग ने एस.बी.आई. लाइफ इंश्योरैंस कम्पनी को कहा है कि बीमा कवर के रुप में काटी गई 41,059 रु. की राशि ब्याज सहित वादी को लौटाए, आयोग ने बीमा कम्पनी पर 65 हजार रु. का हर्जाना भी लगाया।**

जयपुर, 4 सितंबर। जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने होम लोन के बीमा कवर के रूप में वसूली गई राशि को उपभोक्ता को लौटाने के दौरान कटौती करने को सेवा दोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने एस.बी.आई. लाइफ इंश्योरैंस कंपनी को कहा है कि वह काटी गई 41,059 रुपए की राशि ब्याज सहित लौटाए। इसके साथ ही आयोग ने बीमा कंपनी पर कुल 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना ने यह आदेश जगमोहन सिंह यादव के परिवाद पर दिए।

परिवाद में कहा गया कि परिवादी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा मीडिया का आकलन स्वीकार करने को तैयार नहीं जम्मू-कश्मीर चुनाव के बारे में

भाजपा का मानना है कि यह सबसे बढिया समय है जब पार्टी अपनी स्थिति सुदृढ़ करेगी

- **जम्मू-कश्मीर चुनाव के सह प्रभारी भाजपा नेता राम माधव चुनाव प्रचार की रणनीति बना रहे हैं, भाजपा की नीति अनुसूचित जाति व जनजाति के वोटर्स को साधने की है।**
- **पहली बार राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा में एस.सी./एस.टी. समुदायों के लिए सीटें रिज़र्व की गई हैं और भाजपा को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है।**
- **भाजपा को उम्मीद है कि धारा 370 खत्म करने से पार्टी को जम्मू क्षेत्र में काफी लाभ होगा।**

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। ब्रुनेई व सिंगापुर की अपनी यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जम्मू-कश्मीर में पहली बार सरकार बनाने के प्रयास में जुट जाएंगे और इसी के तहत अगले सप्ताह उनकी तीन रैलियाँ प्रस्तावित हैं। इनमें से दो रैलियाँ जम्मू क्षेत्र में होंगी, जिसमें डोडा भी शामिल है, जहाँ, हाल के महीनों में कई आतंकवादी गतिविधियाँ हुई हैं। तीसरी रैली कश्मीर क्षेत्र में होगी।

संभावना है कि प्रधानमंत्री 8 सितम्बर के बाद इस केन्द्र शासित प्रदेश का दौरा करेंगे।

सन् 2014 में हुए गत विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 25 सीटें जीती थीं और महबूबा मुफ्ती की पार्टी 28 सीटों पर विजयी रही थी।

तथापि, इस बार चुनाव विश्लेषकों की भविष्यवाणी भाजपा के लिए उतनी फायदेमंद नहीं है। "लोकपोल" के अनुमान के अनुसार, नैशनल कॉन्फ्रैंस - कांग्रेस गठबंधन को आसान जीत मिलेगी, जबकि 90 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा 20 सीटों पर सिमट जाएगी।

तथापि, भाजपा के "थिंक टैंक" का सोच अलग है। पार्टी का मत है कि तीन कारक हैं, जो इस बार भाजपा के सत्ता में आने की संभावना को मजबूत करते हैं। पहला, धारा 370 तथा 35 ए निरस्त होने के बाद क्षेत्र में, विशेषरुप से जम्मू क्षेत्र में, भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ी है। दूसरा, चुनाव आयोग ने 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर- विधानसभा में एस.सी./एस.टी. के लिए सीटें आरक्षित की हैं। तथा अंतिम कारक है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निरंतर बनी हुई लोकप्रियता।

भाजपा की धारणा है कि बहुकोणीय प्रतिस्पर्धा में एन.सी.-कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में निर्दलीयों तथा छोटी पार्टियों के मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है।

इसके अतिरिक्त, राम माधव तथा अनुराग सिंह ठाकुर जैसे भाजपा नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेवारी दी गई है और भाजपा युवाओं के अलावा, एस.सी. व एस.टी. मतदाताओं को आकर्षित करने की रणनीति पर काम कर रही है।

हाल के दिनों में, टिकटों के बंटवारे को लेकर जम्मू क्षेत्र में काफी अन्तर्कलह सामने आई है, जबकि पार्टी की कश्मीर शाखा भी, घाटी की 16 सीटों के लिए केवल 8 प्रत्याशी मैदान में उतारने के पार्टी नेतृत्व के निर्णय को लेकर असंतुष्ट तथा व्यथित है। इन सीटों पर, पहले चरण में, 18 सितम्बर को मतदान होना है।

तथापि, भाजपा के चुनाव सह-प्रभारी राम माधव को विश्वास है कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान में पहली बार दिखी "गोले दागने वाली" अनोखी फंगस

- **दक्षिणी राजस्थान के मांडलगढ़ क्षेत्र के राजपुरा गांव में "स्पिरोबोलस जयसुखियेंसिस" नाम की फंगस को छूते ही छोटे-छोटे काले रंग के गोले, यानी बीजाणुओं की तेजी से बरसात करती है, मानो तोप गोले दाग रही हो।**

उदयपुर, 4 सितम्बर (वार्ता)। दक्षिणी राजस्थान के मांडलगढ़ क्षेत्र के राजपुरा गांव में जैव विविधता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण खोज हुयी है और राज्य में पहली बार "स्पिरोबोलस जयसुखियेंसिस" देखी गयी है।

फाउंडेशन साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी के फील्ड इकोलॉजिस्ट डॉ.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दो राज्य, एक संकट, दो हीरो!

कुछ घंटों में 30-34 सैन्टीमीटर बारिश ने आंध्र व तेलंगाना को भारी विपदा में घेर लिया

- **तेलंगाना में 16 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा आंध्र में विजयवाड़ा में दो तीन लोगों ने मकानों की छत पर शरण लेकर जान बचाई।**
- **चंद्रबाबू नायडू ने राजधानी अमरावती का सचिवालय छोड़कर विजयवाड़ा के जिलाधीश कार्यालय को अपना ऑफिस बनाया, दो-तीन रात, बस को ही अपना निवास बनाया, जनता के बीच में 24 घंटे रहकर विपदा प्रबंधन में लगे रहे।**
- **तेलंगाना के मु.मंत्री रैवन्त रेड्डी भी वारांगल शिफ्ट हो गये तथा आंध्र व दिल्ली जहाँ प्रतिस्पर्धी पार्टी भाजपा की सरकार थी, से भी सम्पर्क किया और राहत कार्यों की सामग्री व साधन मांगने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं रखी।**

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 अगस्त। दो तेलुगू भाषी राज्यों- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अतिवृष्टि के चलते दोनों मुख्यमंत्री- एन. चंद्रबाबू नायडू तथा रैवन्त रेड्डी अपने-अपने राज्यों में बचाव, राहत और पुनर्वास के लिये पूरी तरह सक्रिय हो गये हैं। नायडू कल से विजयवाड़ा में तेजी से बचाव कार्य में जुट गये हैं। वे बस में बैठकर तथा ज़मीनी स्तर पर उतर कर हर चीज़ पर नज़र रख रहे हैं। उन्होंने एन.टी.आर. जिला कलेक्टर के कार्यालय को अपना अस्थाई कार्यालय बना लिया है तथा खुद ही राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अपने सुरक्षा-अधिकारियों की सलाह की अनसुनी करते हुये, बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों के कई दौरे किये हैं तथा वे असाधारण रूप से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं क्योंकि भारी वर्षा के कारण कई क्षेत्र जलमग्न हो गये हैं तथा अनेकानेक लोग बेघर हो गये हैं। इस जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, चार बार मुख्यमंत्री रह चुके नायडू की प्रशासनिक शैली अलग और स्पष्ट दिखाई दे रही है। वर्ष 2014 में, जब "हुद-हुद" चक्रवात से विशाखापट्टनम शहर और बंदरगाह पूरी तरह तबाह हो गये थे, उस समय बंदरगाह नगर का सतत निरीक्षण करने के लिये वे विशाखापट्टनम में डेरा डाले रहे थे और पूरे शहर के पुनर्निमाण का काम किया था।

सप्ताहांत के समय तीन दिन से चल रही भारी बरसात ने आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में जबरदस्त तबाही की थी। कुछ ही घंटों में बादल फटने से 29 से 34 सेमी. तक हुई बरसात होने के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई। बाढ़ के पानी के ओवरफ्लो के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों पर टैफ्रिक रूक गया था तथा बड़ी संख्या में रेल-सेवायें रद्द कर दी गई थी। बाढ़ से हुई यह तबाही उस समय और विकराल रूप में आ गई, जब विजयवाड़ा से गुजरने वाली बुडामेरू स्ट्रीम के कारण बहुत सी कॉलोनियाँ जलमग्न हो गईं तथा करीब दो लाख लोगों ने अपनी जान बचाने के लिये अपनी इमारतों के टैरेस या फर्स्ट फ्लोर पर शरण ली।

बाढ़-पीड़ित लोगों की दुर्दशा से विचलित हुये मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने संकट की इस घड़ी में चुस्त-दुरुस्त नेतृत्व उदाहरण पेश किया। वे अपने कार्यालय एवं प्रशासन को सचमुच ही अमरावती से विजयवाड़ा ले गये जिससे वे बाढ़-प्रभावित क्षेत्र के निकटतम स्थान पर रह सकें।

अधिकारियों को राज्य में बाढ़ की चुनौती का मुकाबला करने के निर्देश देते हुये, वे फील्ड-स्तर पर होने वाले कामों में कूद पड़े। एक विशेष बस में बैठकर मुख्यमंत्री स्थिति को संभालने की कार्यवाही में प्रशासन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तब तक दौरे करते रहेंगे, जब तक सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो जाती।

भारी बरसात के कारण विशेष रूप से कृष्णा एवं गुन्टूर जिलों में भयंकर तबाही हुई है। बुडामेरू में आई बाढ़ से विजयवाड़ा के सिंह नगर, नन्दापुरी तथा निचले इलाके में बसी अल्प बस्तियाँ जलमग्न हो गई हैं तथा बाढ़ से दो लाख लोग प्रभावित हुये हैं।

मुख्यमंत्री नायडू ने आधी रात के समय बाढ़-पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया, ताकि प्रभावित लोग आश्वत हो सकें कि प्रशासन उनका पूरा-पूरा ध्यान रखेगा। अगले दिन सुबह वे यह जानकारी लेने के लिये उस इलाके में गये कि उन लोगों खाना तथा पीने का पानी पहुँचा है या नहीं।

मुख्यमंत्री नायडू ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह से सम्पर्क किया तथा उन्हें वर्तमान बाढ़ संकट की स्थिति से अवगत कराया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वायनाड पीड़ितों के लिए राहुल ने एक माह की सैलरी दान की

- **राहुल गांधी ने बुधवार को इस बात की जानकारी देते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं।**

नई दिल्ली, 4 सितम्बर। केरल के वायनाड में आई भयानक बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आगे आए हैं। उन्होंने वायानाड के बाढ़ पीड़ितों के लिए अपनी एक महीने की तनख्वाह दान कर दी है। राहुल गांधी ने बुधवार को इस बात की जानकारी देते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं। गौरतलब है कि राहुल गांधी पिछली लोकसभा में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)